

या अल्लाह!

शाही मस्जिद हटाने पर बवाल



उज्जैन , 28 सितंबर (एजेंसियां)। उज्जैन के शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को निराकृत कर दिया। याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने बताया कि सड़क के लिए तीन फीट जगह देने और कुछ दुकानों को हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर स्थानांतरित किया जाएगा तथा दुकानदारों को दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस

इससे पहले सोमवार सुबह मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को हटाने की कार्रवाई के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोपहर होते-होते एक बार फिर पथराव शुरू हो गया।

पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय कार्रवाई रोक दी गई। इसके बाद स्थिति धीरे-धीरे शांत हो गई।

तीन थानों में 20 लोगों के खिलाफ मामला, 15 हिरासत में पुलिस ने तीन थानों में 20 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आठ लोगों को नामजद किया गया है। नामजद आरोपियों में पांच सामाजिक माध्यम प्रभावक भी शामिल हैं। **8**

इसी रूट पर थे खड़े हनुमान

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण को लेकर शाही मस्जिद का मामला विवाद में आ गया है। छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का प्रस्तावित सड़क सीमा में आने वाला करीब 11 फीट हिस्सा हटाया जाना है। सोमवार को कार्रवाई शुरू होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया और पुलिस पर पथराव किया। इससे पहले भी धार्मिक स्थलों को लेकर चर्चा में रहा है। कंटाल से छत्री चौक के बीच सड़क चौड़ीकरण की जद में करीब 170 वर्ष पुराना खड़े हनुमान मंदिर भी आया था। मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसको लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ। हाईकोर्ट के आदेश में भी इस मार्ग पर स्थित अन्य संरचनाओं और सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस



मार्ग पर अधिकांश बाधक संरचनाएं हटाई जा चुकी थीं और संबंधित मस्जिद की संरचना प्रमुख शेष बाधाओं में शामिल थी। **8**

खैरताबाद उप-चुनाव SIR के बाद

हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। तेलंगाना विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को राजपत्र अधिसूचना जारी कर खैरताबाद से विधायक दानम नागेंद्र को 23 अप्रैल 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया है।

इससे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह उपचुनाव चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के बाद राज्य का पहला चुनावी परीक्षण होगा।

यह अधिसूचना तेलंगाना उच्च न्यायालय के 18 सितंबर के आदेश के बाद जारी की गई, जिसमें नागेंद्र को दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया था। नागेंद्र दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में खैरताबाद से बीआरएस प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे, लेकिन इसके बाद अप्रैल 2024 में उन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था।

खैरताबाद उपचुनाव तेलंगाना में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के नवंबर में पूरा होने के बाद राजनीतिक दलों के लिए पहला चुनावी परीक्षा होगा। इस प्रक्रिया से क्षेत्र के मतदाता आधार में पहले ही पर्याप्त बदलाव आ चुके हैं।

एसआईआर से पहले खैरताबाद में 2,93,667 मतदाता थे। मसौदा मतदाता सूची में 1,70,195 नाम शामिल थे, क्योंकि इसमें शुरू में उन मतदाताओं के नाम थे जिन्होंने गणना फॉर्म जमा किए थे। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत्यु और डुप्लीकेट (एसडीडी) श्रेणी के तहत मसौदा सूची से 1,23,472 नाम हटा दिए



गए हैं। इनमें से 95,082 मतदाताओं को क्षेत्र से स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की श्रेणी में रखा गया है।

मतदाता सूची संशोधन से बड़ी संख्या में नोटिस भी जारी हुए हैं। 81,404 मतदाताओं को उनके नाम एसआईआर 2002 डेटाबेस से न जुड़े होने या गणना फॉर्म में विसंगतियों के कारण नोटिस दिए गए हैं। उपचुनाव में वोट डालने के योग्य मतदाताओं की अंतिम संख्या दावों और आपत्तियों के निपटारे तथा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची पर निर्भर करेगी।

दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कुल 2,96,036 मतदाताओं में से 1,53,730 वोट (52.34 प्रतिशत) पड़े थे। तब बीआरएस टिकट पर चुनाव लड़ रहे नागेंद्र ने 67,368 वोट हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी पी. विजय रेड्डी को हराया था, जिन्हें 45,358 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी चितला रामचंद्र रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 38,094 वोट मिले थे। नागेंद्र की अयोग्यता की अधिसूचना अब चुनाव आयोग के लिए खैरताबाद उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर देती है।

18 की उम्र जरूरी सोशल मीडिया अकाउंट

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खातों को लेकर वैधानिक व्यवस्था बनाने पर विचार करने को कहा। अदालत ने कहा कि नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानूनों का पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों को करना होगा। भारतीय कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग होते हैं और स्वतंत्र रूप से कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यह शर्त केवल दिशानिर्देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से सूचना प्रौद्योगिकी के मध्यस्थ नियमों के तहत इसे वैधानिक रूप देने पर विचार करने को कहा। अदालत ने केंद्र से यह भी विचार करने को कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को किस तरह कानूनी ढांचे में शामिल किया जा सकता है।

8

त्रिभाषा नीति छठी क्लास को भी छूट

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तीन-भाषा नीति को लेकर वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान में कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह तीन-भाषा नीति में समान छूट दी जाए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी। कोर्ट ने कहा कि अचानक भाषा बदलने की स्थिति में कक्षा 6 के छात्रों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्हें भी समान राहत दी जानी चाहिए। वर्तमान कक्षा 6 के छात्र तीसरी भाषा पढ़ने की व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, लेकिन उन्हें इस भाषा में आगे चलकर सीबीएसई की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। उन्हें अपनी मौजूदा दो भाषाओं के साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा लेने की सुविधा भी दी जा सकती है।

पहले केंद्र सरकार ने वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को इस वर्ष से छूट देने का विरोध किया था। केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस वर्ष कक्षा 6 को छूट देने के पक्ष में नहीं है और छात्रों को इसी वर्ष से तीसरी भाषा पढ़नी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रुख को स्वीकार नहीं किया और कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों के समान राहत देने का निर्देश दिया।

8

UPI को सुप्रीम इंडी 2000 से अधिक पेमेंट पर चार्ज तय

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतान वाले यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने की केंद्र सरकार की व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी कर इस शुल्क की कानूनी और नीतिगत आधार पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने अधिवक्ता अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में 2,000 रुपये की सीमा तय करने और यूपीआई तथा रुपे कार्ड के लिए अलग-अलग नियम बनाए जाने पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने नई शुल्क व्यवस्था को रद्द करने की मांग की है।

अधिवक्ता अंजन दत्ता ने अपनी जनहित याचिका में सवाल उठाया कि 2,000 रुपये की सीमा ही क्यों तय की गई और यूपीआई तथा रुपे कार्ड के लिए अलग-अलग व्यवस्था क्यों रखी गई। याचिका में दावा किया गया कि सरकार ने पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा और स्पष्ट वैधानिक प्रक्रिया के बिना यह शुल्क व्यवस्था लागू की है।

8

भारत-पाक मिलाप! सिंदूर के बाद पहला इस्लामाबाद दौरा

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन (एस-सीओ) के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में एक साथ शामिल हुए। 28 से 30 सितंबर तक होने वाली इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय समन्वयक और संगठन के सचिवालय के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक आल-गेक डिमरी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. एम. फैसल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य तनाव के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान में यह पहली एससीओ बैठक में भागीदारी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर अक्टूबर 2024 में एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद दोनों देश एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भागीदारी जारी रखते हैं। बैठक में एससीओ के तहत सहयोग और समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इनमें पाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, **8**



2.80 लाख सैलरी, इस्तीफ़ा भारी पड़ा बाँस ही फर्जी!

ग्वालियर/कानपुर, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी पाने के लिए अनुभव और वेतन से जुड़े दस्तावेज जमा करना सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस प्रक्रिया को पार कर लिया। उसने खुद को एक बड़े समूह का पूर्व कर्मचारी बताया, लाखों रुपये महीने का वेतन पाने का दावा किया और इसी आधार पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी हासिल कर ली।

मामला यहीं नहीं रुका। कंपनी ने उसके काम को देखते हुए उसे समूह उपाध्यक्ष के पद से आगे बढ़ाकर समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बिक्री पश्चात) की जिम्मेदारी भी



बाँस का बायोडाटा निकला फर्जी

सौंप दी। करीब नौ महीने तक वह कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता रहा। लेकिन मई 2026 में अचानक उसके इस्तीफे के बाद जब कंपनी ने पूर्ण और अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू की, तो उसके दस्तावेजों की दोबारा जांच की गई। यहीं से उस कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसे उसने नौकरी पाने के समय दस्तावेजों के जरिए तैयार किया था।

2.80 लाख रुपये महीने की सैलरी का दावा

ग्वालियर क्राइम ब्रांच के मुताबिक, आरोपी की पहचान देवेंद्र कुमार दुबे (43), पुत्र रामनरेश दुबे, निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, देवेंद्र कुमार ने 20 अगस्त 2025 को श्रीतुलजा भवानी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में समूह उपाध्यक्ष के पद पर नौकरी हासिल की थी। इसके लिए उसने अपने पुराने अनुभव और वेतन से जुड़े दस्तावेज कंपनी के सामने पेश किए। इनमें एक अनुभव प्रमाण पत्र और लैंडमार्क समूह के नाम से तैयार किया गया बैंक विवरण शामिल था। इस बैंक विवरण में उसकी महीने की सैलरी 2 लाख 80 हजार 670 रुपये बताई गई थी। **8**

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसियां)।

भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन ने रूस में महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन ने रूस में अधिक ऊंचाई और उड़ान से जुड़े परीक्षण पूरे करते हुए 48.5 किलो न्यूटन का अधिकतम ड्राई थ्रस्ट हासिल किया है। यह लगभग 46 किलो न्यूटन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। यानी इंजन ने तय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है।

कावेरी वही जेट इंजन है, जिसे एक समय तकनीकी चुनौतियों के कारण असफल परियोजना माना जाने लगा था। अब इसके बेहतर प्रदर्शन को भारत के रक्षा क्षेत्र और स्वदेशी विमान इंजन विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा



कावेरी ने दुनिया को चौंकाया!

है। कावेरी जेट इंजन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की गैस टर्बाइन अनुसंधान स्थापना ने विकसित किया है। इसे भारत के प्रस्तावित स्टील्थ मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन घातक को शक्ति देने के लिए तैयार किया गया है। प्रणोदन यानी इंजन की क्षमता के लिहाज से लंबे समय से इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण प्राप्ति का इंतजार किया जा रहा था।

क्या परीक्षण किया गया?

इस इंजन को कावेरी डेरिवेटिव इंजन के नाम से जाना जाता है। यह मूल कावेरी इंजन का आफ्टरबर्नर रहित संस्करण है। इसे ऐसे विमानों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें आफ्टरबर्नर से मिलने वाली अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ड्राई थ्रस्ट का मतलब बिना आफ्टरबर्नर के मिलने वाला थ्रस्ट यानी प्रणोदन बल है।

ये परीक्षण रूस के दो प्रमुख संस्थानों में किए गए। पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स (सीआईएमए) और दूसरा प्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सीआईएमए में इंजन को ऐसी परिस्थितियों में परखा गया, जो अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने जैसी स्थितियों के अनुरूप थीं। **8**

संपादकीय

ट्रंप-जिनिपेंग वाता

वैसे तो चमक-दमक और जोरदार मेहमाननवाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनोल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वॉशिंगटन में ह

मुलाकात प्रथम दृष्टया शानदार नजर आती है। लेकिन हकीकत में इस सफ्ट को कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आया। दिल मिलने न मिले हाथ मिलाते की तर्ज पर एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ किन्तीन गहराई तक आपस में जुड़ी हुई हैं। उनमें हम मतभेद और मुखर प्रतिहिंदा आज भी कायम हैं। वाता को स्पष्ट परिणाम उन्ने बीबी व्यापारिक युद्ध विराम का आगे बढना है। हालाँकि, दोनों देशों के व्यापारिक मामलों को लेकर बुनियादी विवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिका ने कई तरह के टैरिफ चीन पर थोपे हैं। अमेरिकी सामान का चीन द्वारा खरीदने का विवाद, रियर-अर्थ सल्लाई और चीन को दी जाने वाली उन्तत तकनीकों पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। लेकिन दोनों देशों के कारोबारियों में ये सोच लिये थोड़े समय की राहत को स्थायी समझौता नहीं माना जा सकता। हालाँकि इसका सबेरे बावजूद इस शिखर सम्मेलन के संकेतिक महत्व को खींचाकर करना होगा। जिस तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए रेड कोर्ट बिछाया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह परंपरा का

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिन्पिंग के बीच वॉशिंगटन में हुई मुलाकात प्रथम दृष्टया शानदार नजर आती है। लेकिन परीक्षा में इस संमित का कोई दोसक हाकान नजर नहीं आया। दिल मिलेन न मिले शह मिलाने की तर्ज पर एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ किन्ती गहराई तक आपस में जुड़ी हुई हैं। उनमें गहरे मतभेद और मुखर प्रतिस्द्धिता आज भी कायम है। वार्ता का स्पष्ट परिणाम उनके बीच व्यापारिक युद्ध विराम का आगे बढ़ना है। हालांकि, दोनों देशों के व्यापारिक मामलों को लेकर बुनियादी विवाद अभी कम नहीं हुए हैं। अमेरिका ने कई तरह के टैरिफ चीन पर थोपे हैं, अमेरिकी सामान का चीन द्वारा खरीदने का विवाद, रथ- अर्थ स्पलाई और चीन की दो जी जाने वाली उन्नत तकनीकों पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। लेकिन दोनों देशों के कारोबारियों के लिये थोड़े समय की राहत को स्थायी समझौता नहीं माना जा सकता। हालांकि इसके बावजूद इस शिखर सम्मेलन के सकेत महत्व को स्वीकार करना होगा। जिस तरह चीन राष्ट्रपति शी जिन्पिंग के लिए रेड कोर्पो बिछाया गया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह परंपरा को नजरअंदाज करके हवाई अड्डे पर शी जिन्पिंग का स्वागत करने गए, उससे प्रतिस्पर्धी दौर में चीन के बढ़ते प्रभाव का ही पता चलता है। ट्रंप ने गर्व के साथ व्हाइट हाउस के नये रूप में तैयार परिसर को उन्हें दिखाया और शानदार राजकीय भोजन का भी आयोजन किया। हालांकि, ताड़वान के मामले में बहुत कुछ दांव पर लगा था। शी ने वॉशिंगटन से ताड़वान की आजादी का विरोध करने और इस मुद्दे को संवेदनशील ढंग से संभालने का भी आग्रह किया। जिसे चीन चीन की समझदारी मानता है। हालांकि, अमेरिका ताड़वान के मुद्दे पर एक अस्पष्ट नीति की अपनाना हू है। एक ओर अमेरिका ताड़वान का अपनी रक्षा करने की नीति का समर्थन तो करता है, लेकिन उसकी प्रंग्रभुता को औपचारिक नीति नहीं देता। शी मायने में इस बहाने शी ने डोनाल्ड ट्रंप को चीन की प्राथमिकताओं से अवगत कराय। उन्होंने अमेरिका को संकेत दिया कि चीन ताड़वान के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वास्तव में चीनी रणनीति का सिद्धांत उस अवधारणा पर केन्द्रित है, जो टकराव के खतरे को बताती है। शी हारिता तब पैदा होता है जब कोई स्थापित चीन के शक्ति पर उसी शक्ति का सामना करना पड़े। वहाँ चीनी राष्ट्रपति ने मौजूदा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच सैन्य बातचीत का अपरिहार्यता को बताया। साथ ही किसी भी तरह के संकट को टालने में निमित्त मजबूत तंत्र बनाने का भी आह्वान किया। निस्संदेह, इस तरह का पहल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉशिंग और वॉशिंगटन के मध्य अहम पहल वॉशिंग और वॉशिंगटन के मध्य अहम पहल केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। बल्कि सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों तक विस्तृत है। सही मायने में कृत्रिम बुद्धिमान खोज है जो तारी तरो होइ न इस अंतर को दर्शाया है। आज के बढ़ते तेजी से विकसित होतों एआई तकनीकों के तरह तरह- तरह की आशंकाएं पैदा हुई हैं। दुनिया में एआई के शोध- अनुसंधान की गति का धीमा करने की मांग की जा रही है ताकि विश्व मानवता के लिये नया संकट पैदा न हो। एआई और ट्रंप ने एआई को नियमों से बचाने पर जोर दिया है, वहाँ दूसरी ओर शी जिन्पिंग ने तबके दिया कि एआई को ईसानी फिटिंग में रखना जाना चाहिए। इसकी भूमिका सिर्फ मानव हित में कामगमन नजरिये में एआई को लेकर भिन्न-भिन्न महारतियों से स्पष्ट होता है कि भविष्य में इस क्षेत्र में सहयोग शायद मुश्किल होगा। दरअसल दोनों को भय है कि यदि एआई का नियमन किया न जाये तो वे अपने-अपने देशों के हितों को

पीछे रह सकता है। निस्संदेह, इस शिखर सम्मेलन से भले ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल न हुई हो, इसके बावजूद इस मुलाकात का अपना एक विशेष महत्व तो है। शिखर सम्मेलन का महत्व इस बात को लेकर भी है कि वाशिंगटन और बीजिंग अपनी लगातार बातचीत में व्यावहारिक स्थिरता में बदल सकते हैं। निस्संदेह, दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता को टकराव में बदलने से रोका जाना चाहिए।

कुछ

अल

श्रद्धा से जुड़ा दान पितृ पक्ष की पहचान

भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में पितृ पक्ष का विशेष स्थान है। यह वह पखवाड़ा है जब हिंदू परिवार अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से अपने प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारा पूर्वज पुण्य लोक में आकर अपने पेशेजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किया गया दान केवल आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह जीवन में कृतज्ञता, सेवा और सामाजिक सामंजस्य का संदेश भी देता है। इसलिए पितृ पक्ष में दान का विशेष महत्व माना गया है। कुछ वस्तुओं के दान को तो महानादों की श्रेणी में रखा गया है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में हम जो भी अपने पितरों के लिए अर्पित करते हैं, वे उस सुख रूप में स्वीकृत करेंगे। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृगण निराह्वास किए अपने-अपने महलकों के यहां पहुंचेंगे और अपने पंद्रह दिनों तक वहीं विद्यमान रहेंगे हैं।

दृष्टि

कोण

देश की राजतन्त्र

पुरानी व्यवस्था निरंतर बजल रही है और उसकी जगह नया निजाम ले रहा है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ऐसा लगा कि बुजुर्ग हों या युवा, दोनों ही, सत्ताधारियों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम, पंजाब की राजनीति के वयोवृद्ध नेता, 84 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 'द ट्रिब्यून' को बताया कि 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीमा पार से ड्रोने के जरिए नशा स्मगलिंग का मुद्दा उठाया था; जब कान नहीं धरा तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 'दिल्ली को पंजाब की समझ नहीं। सिंह ने कहा कि भाजपा ने राज्य में नीति और राजनीति के मामलों पर उनसे कभी सलाह नहीं ली और पार्टी में शामिल होने से उन्हें कोई लाभ नहीं

हुआ। विरप्प नेता की नाराजगी के अलावा, बीते गुरुवार दिल्ली में युवाओं की 'कोकॉकच जनता पार्टी' (सीजेपी) की प्रेस वार्ता में भी आक्रोश ऐसा ही था। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। यह मांग 'इंडियन एक्सप्रेस' के खुलासे के बाद आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए वोटघंटे के नाम हटाए जाने की जानकारी के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां प्रमुख सवाल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सीमाओं को लेकर है- और क्या उम्र का इससे लेना-देना होना चाहिए। क्या बीजेपी अमरिंदर द्वारा अपनी पार्टी की आलोचना और पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता पर कोई ध्यान देना चाहेंगे, वह भी काफी अहम विधानसभा चुनावों से पहले? इतना

नीति में बदलाव के सवाल



ही महत्त्वपूर्ण यह कि क्या आप उस संगठन की मांगें अनदेखा कर सकते हैं जो कोई सिपायी दल भी नहीं? खासकर तब, जब पिछले बार सीजेपी के प्रदर्शन पर सख्ती की थी, तो शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा था?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद उठे हमामों के बीच खामोश संदेश पर विचार जरूरी है, हालांकि राजसत्ता अब खुद को संभाल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के लिए सीजेपी द्वारा 48 घंटे की

फिर हो मंथन

मोहलत जैसे-जैसे पास आती गई, जंतर-मंतर पर फिर बैरिकेड्स लगा दिए। ज्ञानेश कुमार ने अपने देरती रह कर दिए। न केवल विषय, बल्कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे भाजपा के सहयोगी भी अब दबाव डाल रहे हैं वॉ मांग कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त 'लोगों के मन में बनी गलत छवि पर ध्यान देकर' करें। निस्संदेह, देश 'दो हिस्सों' में बंट रहा है। दिल्ली में जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के बाद सीजेपी ने धीरे-धीरे दायरा बढ़ाया- आदिन सीजेपी की सोशल मीडिया पर वीडियो दिखती हैं जो उनकी '#स्कूल ठीक करे' मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों की बदहाली बताती हैं; खुद दफतल ससुदाय से संबंधित अभिजीत दीपक की कोशिश है कि आईआईटी बॉम्बे में छात्र की मौत के बाद ध्यान जाति, वगैरह पर चर्चा से परे मानसिक सेहत पर रहे। सीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने मीडिया को अपना काम करने पर मजबूर किया- चाहे सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछना हो या विपक्ष से। सवाल उठता है कि सिवाय आम आदमी पार्टी के, जिसने पंजाब में अपने 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' परियोजना पर काफ़ी मेहनत की है (भले ही नतीजे मिले-न मिले रहे) किसी भी अन्य सिआइसी दल ने शुल्क जैसे अहम मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सिवाय उस वक़्त, जब वे निजी विश्वविद्यालय स्थापित करती हैं व सस्ती दरों पर संसाधन उनके हवाले करती हैं? सीजेपी हमें आईना दिखा रहा है कि यह सब आपके आस-पास हो रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। सच तो यह कि हमने देखा था, लेकिन आप तो ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं हमारा योदान भी रहा, या अत्यधिक निराशावादी बने रहे, या फिर परवाह नहीं रही।

जाला स्तर पर सहायक अधिकारियों को संस्थागत व्यवस्था की गई है। क्योंकि अधिकारिणीनितिकी की कितना भी नई, उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव तब और ज्यादा से उत्पादन तक रास्ता खुलें—तभी किसान की पहचान वास्तविकता में आती है। शक्ति बनेगी। नाम बदलने से कभी-कभी पूरी जिंदगी का अर्थ बदल जाता है। महिला के हाथ में किसान प्रमाणपत्र आते ही सरकारी दफ्तर में उसकी पहचान किसी किसान की पत्नी या परिवार की महिला नहीं, स्वयं किसान की होती। यह बदलाव देता है। पहचान आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास निणय की ताकत बढ़ाता है। अधिक संकेत को हम मोसम, कर्ज, लागत और बाजार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसके भीतर महिलाओं के श्रम की अदृश्यता का संकेत भी है। जिस मेहनत का सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं, वह स्वतंत्र आर्थिक शक्ति कैसे दे? महाराष्ट्र का कानून इसी अनदेखे श्रम को पहचान और रिकॉर्ड देने की कोशिश है। किसान की पहचान और जमीन का मालिकाना—यह अलग अधिकार है। महिला किसान प्रमाणपत्र से जमीन उसके नाम नहीं होगी, उदाहरण के तौर पर नहीं मिलेगा और भूमि अभिलेख भी नहीं बदलेगा। इसलिए यह कानून भूमि का पुनर्वितरण नहीं है। आलोचना यह है कि महिलाओं की पहचान नहीं, लेकिन संपत्ति का पुनर्वितरण नहीं हुआ। यह सीमा है, पर कानून को निरर्थक नहीं बनाती।

भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 5 गुना तक बढ़ सकती है

भारत चल पड़ा है नई औद्योगिक क्रांति के पथ पर

भारत में आज एक नई औद्योगिक क्रांति
एगसथोन्नी है। यह निम्न अपेक्षित

की एक जाने मानी निवेश बैंक- जे प्रोजीज ने व्यक्त किया है। भारत में, विशेष रूप से डाटा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से करोड़ों अमेरिकी डॉलर का निवेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में डाटा केंद्रों की स्थापित करने के उद्देश्य से एक सस्का की ओर से पैक में भारी भरकम छूट भी प्रदान की जा रही है। अतः भाग्यशाली में डाटा केंद्र स्थापित करने की तो जैसे हांडू की मछली है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में डाटा केंद्रों की क्षमता दोगुनी हो चुकी है एवं आगे आने वाले 5 वर्षों के दौरान यह क्षमता बढ़कर 10 GW हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। वैश्विक स्तर पर डाटा केंद्र अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। साथ ही, भारत में समीकंड्रक्टर उत्पादन इकाईयों को उत्पादन आधारित प्रोडक्शन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए 1,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है। इसका परिणाम यह है कि समीकंड्रक्टर के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भारत में 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है, और यह आगे भी जारी है। भारत आज उच्च-चुनिद देशों में से एक है, जिनका पास स्पेस क्षेत्र से सम्बंधित नवीनतम तकनीकी उपलब्धि है। भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 5 गुना में तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर एयरो स्पेस क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन के चलते भारत को स्थिति में पहुँच गया है क्योंकि भारत को लासिकी इस्थल इंजीनियरिंग टैलेंट आज भारत में ही उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत आज केवल पुर्णों को इकट्ठा कर उत्पाद बनाने का कार्य करने तक सीमित नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में उच्च स्तर की समीतों का निर्माण भी हो रहा है। 6 वर्षों में मोबाइल कम्प्यूटेशन में घरेलू वैल्यू एडिशन लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। सोलर के क्षेत्र में भारत आज वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सोलर पैनल का उत्पादक देश बन गया है। इसका परिणाम यह है कि वर्तमान में भारत की 35 GW की सोलर



महाना चालू है एवं 100 GW की क्षमता पर निर्माण कार्य चालू है। एशिया की सबसे बड़ी 100 कम्पनियों की सूची में आज भारत की 34 कम्पनियाँ शामिल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर, पूर्व में भारत केवल फार्मा, टेक्स्टायल, चमड़ा उत्पाद, कृषि उत्पाद (मासला, आदि) स्टील, ऑटोमोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही वैश्विक स्तर पर उन्ना उत्पादों का निर्यात करने में सफल हो रहा था परंतु आज स्थितियाँ बदल गई हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे डाटा केंद्र, सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्पेस क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, सोलर क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में उल्लब्ध टेलेटैट एवं ब्राम के भरोसे विश्व की कई बड़ी कम्पनियों के बीच आज भारत में डिशाल वैश्विक कम्पनियों के केंद्रों (जीसीसी) की स्थापना करने की होड़ सी लगी हुई है। ब्रिटेन में फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनी - एस्ट्रा जेनेका ने चेन्नई में एक वैश्वाल वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बैंक ऑफिस कार्यालय पुणे में स्थापित किया है, इस बैंक के पूरे विश्व में बैंक ऑफिस में कार्य कर रहे 11,000 कर्मचारी इन केंद्र का ब्रेन बन गए हैं। अमेरिका के सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मेलोने ने पुणे एवं चेन्नई में वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना की है। ऑस्ट्रिशियल इटैलियंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली बोस्टन की एक कम्पनी ने फरवरी 2026 में हैदराबाद में डिशाल स्तर पर अपने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एवं पुणे में आज 1,70,00 से अधिक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, इन केंद्रों में 19 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। भारत आज आउटसोर्सिंग हब से आगे बढ़कर उच्च स्तरीय टेलेट केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में स्थापित किए गए कुल वैश्विक योग्यता केंद्रों में से लगभग 65 प्रतिशत केंद्र अफ्रीकी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही रीसर्च का कार्य इन केंद्रों पर सम्पन्न हो रहा है एवं टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में नए नए उत्पादों का निर्माण भी इन्हीं केंद्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही अमेरिका की ही एक कम्पनी टूट्रिज ने भी फरवरी 2026 में मुंबई में वैश्विक योग्यता केंद्र की स्थापना की है। अधिक केंद्र को आगे जाने वाले समय में और अधिका विस्तार दिया जाने वाला है। इसी प्रकार, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, साइबर सिक्युरिटी, फार्मा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में कार्यरत अनेक कम्पनियाँ एवं अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। पुणे में, अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों को भारत

संसार में इन्हें हो रहा था, परंतु अब परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। अब एक विशेष रूप से अमेरिका को भारत को रिवर्न बैन इन्हें होने लगा है। क्योंकि दम्पत्य प्रभारन की नीतियों के चलते अनेक देशों में अमेरिका में जाने वाले टैलेंट का अमेरिका में रहना अब मुश्किल हो रहा है। अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों में पूँजीवाद एवं साम्यवाद की नीतियों के चलते देशों में जन्म दर भी लगातार कम हो रही है। इन देशों में समाज में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। विवाह जैसी और पवित्र संस्था को पिछमी देशों में केवल मौज मस्ती का माध्यम बना दिया गया है। केवल कामकाज के लिए विवाह नहीं किया जाता है जबकि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। भारतीय दर्शन में अपने कुल को और बढ़ाने के लिए विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। जबकि, पिछमी देशों में आज विवाह को आवश्यक नहीं नहीं माना जा रहा है बल्कि वहाँ के नागरिक लिंव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे हैं। इन देशों में नराला की दर में अचलन तथा वृद्धि दस हो रही है। इन देशों में जीवन शैली यानि यापन की लागत बहुत अधिक महंगी हो गई है। साथ ही, पिछमी दर्शन में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, जहाँ कुछ भी योगाना है केवल इसी जन्म में सम्पन्न करना है। अतः इन देशों में अपनी पीढ़ी को और बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने आवश्यक नहीं समझा जा रहा है। इन देशों में समाज की जीवन शैली भी इस प्रकार की बन गई है कि केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें एवं अपनी काया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने चाहिए, परिवार पर एवं समाज पर किसी नागरिक का ध्यान बहुत कम है। पिछमी देशों में नागरिक, “मैं और केवल मैं” किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी रह सकता हूँ, इस विषय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यह विशेषताएँ पूँजीवाद एवं साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत मुखर रूप से उभर का सामने आती हैं। बच्चे पैदा करने का निर्णय भी बहुत एवं खर्च की दृष्टि के सामने रखकर लिया जा रहा है। चूँकि मैं अपने बच्चे पर होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकता हूँ अतः मैं बच्चे पैदा ही नहीं करता हूँ।

देश

दुनिया से

जन्मशताब्दी वर्ष में एक युगपुरुष का पुण्य

एक बहुत सुंदर सुभाषित है, 'वृक्ष कबहुं नहीं फल भवै, नदी न संचै नीर। परमास्थ के कारण, साधुन धरा शरीर'। अभिप्राय है कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदी अपना जल अपने पास नहीं रखती। इसी तरह, संत स्वभाव के लोग भी स्वयं को प्राथमिकता न देते हुए, अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। हमारे श्रेष्ठियों ने यही सिखाया है कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन का महत्व व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक होता है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का जीवन इस भावना का पुष्प उदाहरण है। 27 सितंबर से हम स्वर्णाश्रम अशोक सिंघल जी का जन्म-शताब्दी वर्ष मनाते जा रहे हैं। यह महान विभूति के सम्मान का सुअवसर है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना, सांस्कृतिक जागरण और दशकों तक समर्पित भाव से समाज-संरचना के कार्यों को अगे बढ़ाया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वर्णाश्रम अशोक जी के साथ लंबे समय तक कार्य करने, उनसे सीखने, संवाद करने और उनका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला। मुझे 1984 में प्रथम बार है। तब मैं एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की जिम्मेदारियाँ निभा रहा था। तब मुझे अशोक जी का हस्तलिखित पत्र मिला। उन्होंने आगामी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपीं। तब अशोक सिंघल जी से पत्र पाना भरे लिए एक यादगार क्षण बना। मैंने उन्हें दशकों के दिन-रात काम करते देखा। वे देश के दूर-दूरगर्ग क्षेत्रों की लंबी और कई कठिन यात्राएँ किया करते थे। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में जि जना उद्देश्ये प्रिय था। वे चिंतन करते थे कि समाज के वंचित और अल्प पबित में खड़े लोगों के लिए और क्या किया जाए।



संतों और श्रद्धालुओं से भी उनकी बहुत आत्मीयता थी। इससे सांस्कृतिक कोलाचार की उनकी समझ और समृद्ध हुई। समाज हेतु कुछ करना का संकल्प भी और दृढ़ हुआ। दूसरों के लिए जीने की ललक उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ले आई। जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने पूरे उत्साह, अनुशासन और कर्तव्यभाव से निभाया। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से अनेक संस्थाओं और आंदोलनों को मजबूत किया। अपनी ओजस्वी वाणी और अभिव्यक्ति की अद्भुत शैली से वे समाज को मंत्रमुग्ध कर देते थे। साथी कार्यकर्ताओं के प्रति वे अत्यधिक सहानुभूति रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनकी समझी से प्रभावित हुनका नहीं रहता था। साथी-संतों के बीच भी एक काफ़ी सम्मान था। संतगण उनके परामर्श को महत्व देते और उनकी बातों को पूरे आदरभाव से सुनते। मेरी स्मृति में ऐसी दो घटनाएँ उभर रही हैं, जिसे अशोक सिंहल जी के विराट् व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। पहली घटना 1993 की है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के 100 वर्ष पूरे होने के

महिला कौन है? यही सवाल महाराष्ट्र के महिला किसान अधिकार कानून के नामाई, लेकिन खेती को बड़ा हिस्सा संभालती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार राज्य की कृषि कार्यशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि भूमि स्वामित्व में उनका हिस्सा करीब 15 प्रतिशत है। ये आंकड़े उस विरोधभास को उजागर करते हैं, जिसमें श्रम महिला का है। नया कानून कहता है कि किसान होने की कसौटी केवल जमीन का मालिकाना नहीं, खेती में किया गया वास्तविक श्रम भी हो सकता है। यह प्रशासनिक सुधार नहीं, किसान की परिभाषा में बुनियादी बदलाव है। अब किसान कहलाने के लिए जमीन का मालिक होना जरूरी नहीं— खेती में सक्रिय होना पर्याप्त हो सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की वह महिला, जिसमें एक मौसम भी फसल उत्पादन या कृषि-संबंधी गतिविधि में सक्रिय रही है, महिला किसान माना जाएगा। प्रमाणपत्र को पात्र हो सकती है। इसमें खेती के अतिरिक्त यादें, मत्स्य पालन, कुकुट, रेशम और अन्य उद्यम उजड़ भी शामिल हैं। प्रमाणपत्र ग्रामसभा की प्रशंसा पर प्राप्त अभिकारी जारी करेंगे। राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 ने महिला किसानों की पहचान और अधिकारों की दिशा देखाई थी, लेकिन ऐसा राज्य-स्तरीय प्रमाणपत्र नहीं आया था। महाराष्ट्र ने अब उसे बढ़ावा देना शुरू किया है कि खेत में काम करने वाली भूमिहीन महिलाएं भी किसान पदवी प्राप्त कर सकें, जो जमीन अपने नाम होने के कारण अब तक सरकारी व्यवस्था में अदृश्य थीं। पहचान का असली मूल्य तब है, जब वह बढ़ावा देती है महिला किसान प्रमाणपत्र का उपयोग इसी पहचान को खास, फसल बोने के लिए, कृषि योजनाओं, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच में बदलना है। यानी जो महिलाएं अतक खेत में श्रमिक मानी जाती थी, उन्हें आर्थिक व्यवस्था में किसान के रूप में पहचान मिले। इसके लिए राज्य महिला किसान

माष, डिजिल्लेट बटावसे, मुख्यमंत्री की सम्प्रय रही है, महिला किसान प्रमाणपत्र अध्यात्मता वाली सहाय्यतीकरण परिषद की की पात्र हो सकती हैं। इसमें खेती के साथ डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट, रेशम और वन उपज भी शामिल हैं। प्रमाणपत्र ग्रामसभा के प्रस्ताव पर नामित अधिकारी जारी करेगा। राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 ने महिला किसानों की पहचान और अधिकारों की दिशा दिखाई थी, लेकिन ऐसा राज्य-स्तरीय प्रयोग सामने नहीं आया था। महाराष्ट्र ने अब उसे प्रशासनिक रूप देने की पहल की है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि खेत में काम करने वाली भूमिहिन महिलाएं भी किसान पहचान पा सकती हैं।

महाराष्ट्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसके भीतर महिलाओं के श्रेम को अक्षर तक का संकेत भी है। जिस मेहनत का सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं, वह स्वतंत्र आयिक शक्ति कैसे बने? महाराष्ट्र का कानून इसी अनदेखे श्रेम को नहचान और रिकॉर्ड देने की कोशिश है। किसान की पहचान और जमीन का मालिकाना—उसे अलग अधिकार हैं। महिला किसान प्रमाणपत्र से जमीन उसके नाम नहीं होगी, उदात्तराधिकार स्वतः नहीं मिलेगा और भूमि अधिलेख भी नहीं बदलेगा। इसलिए यह कानून भूमि पुनर्धारण का विकल्प नहीं है। आलोचना यह है कि महिलाओं की पहचान मिले, लेकिन संपत्ति का पुनर्वितरण नहीं हुआ। यह सोमा है, पर कानून को निरर्थक नहीं बनाती।

BOOK YOUR DISPLAY CLASSIFIED ADVERTISEMENTS AT

Timings : 9 am to 7 pm

Head office

SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS,

Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,

APIE, Balanagar, Hyderabad - 500 037

City office

SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS,

Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,

APIE, Balanagar,

Hyderabad - 500 037

8688868345

शुभ लाभ

महारे

भाग्यनगर

दैनिक हिन्दी शुभ लाभ, हैदराबाद, मंगलवार, 29 सितंबर, 2026

शुभ लाभ

आपकी सेवा में

शुभ लाभ से जुड़ी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए

मो. 86888 68345 पर संपर्क करें।

भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान में हिंदी कार्यशाला, टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता आयोजित



हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। भाकृअनुप - भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में जारी हिंदी चेतना मास समारोह की शृंखला में आज 28 सितंबर, 2026 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान डॉ. महेश कुमार, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी (राजभाषा), भाकृअनुप-भाश्रीअनुसं ने ई-ऑफिस पर राजभाषा हिंदी के उपयोग की आसान युक्तियां बताई तथा संस्थान में प्रयुक्त टिप्पणियों एवं मसौदा के बारे में जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात कार्यालय के नेमी कार्यों में प्रत्येक वर्ग (वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, आरए, एसआरएफ आदि) के

सहभागियों के द्वारा हिंदी के उपयोग का मूल्यांकन एवं प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान में कार्यरत सभी संवर्ग के लगभग 14 सहभागियों ने उक्त प्रतियोगिता में बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ भाग लिया। श्री शिवप्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी, तथा श्री शेख रुकमान, वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रतियोगिता के निर्णायकों के रूप में नामित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन डॉ. सी तारा सत्यवती, निदेशक के दिशा-निर्देश में डॉ. जिनु जेकब, वैज्ञानिक एवं डॉ. महेश कुमार के द्वारा किया गया।

शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित



हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के मंगलहाट डिवीजन स्थित रामपुरा गोशाला में शहीद भगत सिंह जी की 119वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड सदस्य वाई. नागिरेड्डी द्वारा किया गया, जिसमें अन्न प्रसादन का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए हम शहीद भगत सिंह जी के साहस, बलिदान और देशभक्ति को स्मरण करें तथा उन आदर्शों को बनाए रखें, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। कार्यक्रम में मंगलहाट के पूर्व कॉर्पोरेटर परमेश्वरी सिंह लोध, खैरताबाद डीसीसी उपाध्यक्ष राकेश सिंह, किरण मुदिज, शोभा बाई, पी. शांता, वाई. श्रीदेवी, विष्णु मूर्ति, राजन भाई, गोपाल सिंह, बाकेश सिंह, एच. कुमार सहित अन्य लोगों ने भाग लिया।



मैट्रिक्स स्वर्णकार समाज की वार्षिक साधारण सभा संपन्न

कार्यकारिणी के कार्यों एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत, नवरात्रि उत्सव के लिए बोली संपन्न

हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। मैट्रिक्स स्वर्णकार समाज की वार्षिक साधारण सभा रविवार, 27 सितंबर को शाम 4 बजे गौलीगुडा स्थित मैट्रिक्स में आयोजित की गई। सभा में समाज के अध्यक्ष पवनकुमार मायछ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश प्रसाद जी मायछ, वयोवृद्ध समाजसेवी श्रीमान श्रीनिवास जी बुट्टण, श्रीमान सम्पतकुमार जी परवाल, श्रीमान अशोक कुमार जी कडेल, मार्गदर्शक मंडल के श्रीमान विवेकानंद जी अग्रोया, श्रीमान हुलासचंद जी तोषावड़, श्रीमान हरिकृष्ण जी मायछ, श्रीमान गोविन्द जी झींगा, श्रीमान नारायण जी कडेल, समाज के महामंत्री द्वाराकाप्रसाद मायछ, कोषाध्यक्ष युगलकिशोर जी कडेल, शिक्षा सहायता ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान महावीर प्रसाद जी कडेल तथा महाराजा अजमीरजी चैरिटेबल ट्रस्ट, हैदराबाद-सिकंदराबाद के अध्यक्ष श्रीमान ललित कुमार जी कडेल मंचासीन रहे।



कोषाध्यक्ष युगलकिशोर जी कडेल ने पूरे कार्यकाल का आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसे करतल ध्वनि के साथ पारित कर दिया गया। इसके बाद नवरात्रि उत्सव के लिए बोलियां ली गईं, जिसमें श्रीमान कन्हैयालाल जी एवं राजेश कुमार जी परवाल ने मुख्य यजमान की बोली जीती। इस अवसर पर नवरात्रि, अजमीरुद जयंती एवं दीपावली स्नेह मिलन के संयोजक प्रदीप कुमार जी मांडन, राजेश कुमार जी किष्पल, भीमराज जी मायछ एवं

कन्हैयालाल जी कडेल तथा महाराजा अजमीरुदजी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित कुमार जी कडेल, महामंत्री राजेश कुमार जी परवाल, कोषाध्यक्ष शरद कुमार जी बुट्टण एवं मुख्य यजमान राजेश कुमार जी परवाल का समाज के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सम्मान किया गया। सभा में सहमंत्री विष्णु मायछ, अशोक कुमार मौसूण, भवन मंत्री दामोदर जी कडेल, प्रचार मंत्री चन्द्रशेखर जी रोड़ा, शिक्षा सहायता ट्रस्ट के महामंत्री घनश्याम

मायछ, कोषाध्यक्ष दामोदर ढल्ला, जयकुमार मायछ, पंकज वर्मा, सुरेश परवाल, विकास भामा, मुकेश कुमार डांवर, नवरत्नमल जी जोहरी, नथमल जी रोड़ा, रवि रोड़ा, मालचंद जी मौसूण, कमल कडेल, राजेश कडेल, संतोष अग्रोया, इन्दरचन्द जी अग्रोया, कैलाश चन्द जी, नन्दकिशोर जी परवाल, चन्द्रप्रकाश जी कडेल, पूनमचन्द जी तोषावड़, संतोष कुमार जी कडेल, माणकचंद जी देवाल, गोपाल जी धुण्ड, सागर माहोर, पुरुषोत्तम जी कडेल, राकेश कुमार जी कडेल, मुकेश मांडन, विष्णु जी डांवर, किशोरकुमार जी अग्रोया, देवकरण मायछ, लोकेश वर्मा, राजेश जी रोड़ा, सम्पतकुमार ढल्ला, दिनेश जी मौसूण, प्रेम मायछ, युगलकिशोर जी परवाल, मनोज मायछ, सत्यनारायण जी डांवर, युगलकिशोर जी सहदेव, मोहित, छगनलाल जी परवाल, मनीष सोनी, सविता सोनी, आशीष मायछ, देवकीनंदन जी खजवाणियां, हुक्मीचंद जी, कंचन जी मौसूण, ओम परवाल एवं नन्दा जी सुनालिया सहित समाज के अनेक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं समाजबंधु उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति एवं सहभागिता सराहनीय रही।

हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। लंदन निवासी 57 वर्षीय थैलेसीमिया मेजर मरीज श्री अजय गांधी, जो लगभग छह दशकों से इस बीमारी के साथ जी रहे हैं, आज हैदराबाद थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी (टीएससीएस) पहुंचे और उन्होंने अपने प्रेरक जीवन सफर, अनुभवों, चुनौतियों तथा एक पुरानी रक्त विकार के बावजूद अपनाए गए अवसरों को साझा किया। टीएससीएस के एमआर आरआर ऑडिटोरियम में सैकड़ों थैलेसीमिया और सिकल सेल मरीजों तथा उनके अभिभावकों के साथ उनकी बातचीत बेहद प्रेरक और उत्साहवर्धक रही। इस मौके पर टीएससीएस अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अनुसंधान अधिकारी एवं सचिव डॉ. सुमन जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती रत्नावली, वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक डॉ. पद्मा तथा मनोज रुपानी भी उपस्थित थे। अजय ने अपने बचपन,



स्वास्थ्य चुनौतियों, उपचार यात्रा, करियर, विवाह, पारिवारिक जीवन और थैलेसीमिया मेजर की चुनौतियों के बावजूद संतोषजनक जीवन बनाने में मदद करने वाले संकल्प के बारे में खुलकर बात की। थैलेसीमिया मेजर के साथ अपने लगभग 57 वर्षीय सफर पर विचार करते हुए अजय ने कहा कि यह स्थिति उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह उन्हें परिभाषित नहीं करती। उन्होंने अपने सफर का श्रेय दृढ़ संकल्प, अनुशासित उपचार, उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल, परिवार के समर्थन, आस्था और दृढ़ता को दिया। उनके वर्तमान परीक्षण परिणाम भी दशकों के निरंतर उपचार और देखभाल से हासिल किए गए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान अजय ने टीएससीएस द्वारा थैलेसीमिया मरीजों को एक छत के नीचे पूरी तरह निशुल्क व्यापक सुविधाएं और समर्थन प्रदान करने की सराहना की।

नितिन सिंघानिया के जन्मदिन पर हुई अन्नसेवा



हैदराबाद। राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में नामपल्ली स्थित पब्लिक गार्डन पिलर नंबर 1265-ए के पास सोमवार को नियमित अन्नसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नितिन सिंघानिया के जन्मदिन के अवसर पर विशेष अन्नसेवा की गई। यह सेवा श्री सागरमलजी सत्यनारायणजी सिंघानिया परिवार की ओर से की गई। इस अवसर पर राधे-राधे ग्रुप के सदस्यों ने नितिन सिंघानिया के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगलकामना की। सदस्यों ने कहा कि जन्मदिन जैसे खुशी के अवसर को सेवा कार्य से जोड़ना भारतीय संस्कृतों और मानवता की भावना को मजबूत करता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कार्यक्रम के दौरान नितिन सिंघानिया ने दूरभाष के माध्यम से राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के सभी

सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों के चलते वे स्वयं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसका उन्हें खेद है, लेकिन राधे-राधे ग्रुप ने उनके जन्मदिन को सेवा से जोड़कर जिस आत्मीयता और सेवा भाव का परिचय दिया है, वह उनके और उनके परिवार के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर इस प्रकार की अन्नसेवा उनके लिए यादगार और भावुक कर देने वाला अवसर है। उन्होंने राधे-राधे ग्रुप के सभी सदस्यों को इस सेवा कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर राम प्रकाश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, संजय गोयल, किरण गोयल, जय प्रकाश सारड़ा, भगत राम गोयल, कैलाश केडिया, नंद किशोर अग्रवाल, भाकर राम कुमावत, कमला देवी कुमावत, सुरेश सिंघल, जगन गुप्ता, नंदगोपाल एवं जितेंद्र सहित राधे-राधे ग्रुप के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

गो सम्मान आह्वान अभियान 11 दिसंबर को

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौवंश की रक्षा का संकल्प

हैदराबाद, 28 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। गौमाता को राष्ट्रमाता का पद घोषित करने, गौवंश की रक्षा करने तथा देश में गोहत्या बंद करने के संकल्प के साथ आगामी 11 दिसंबर 2026 को गो सम्मान आह्वान अभियान का आयोजन किया जाएगा। लव फॉर काऊ फाउंडेशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञापन में फाउंडेशन के ट्रस्टी रिद्धीश जागीरदार एवं मुकेश चौहान ने बताया कि गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गौमाता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्र आराध्या का संवैधानिक दर्जा दिलाने, केंद्रीय गोसेवा मंत्रालय की स्थापना तथा एकीकृत केंद्रीय कानून के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026 को संपूर्ण भारतवर्ष के मंडलों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा।



उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल, संगठन अथवा केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति समर्पित है। लव फॉर काऊ फाउंडेशन के चेयरमैन जसमत

पटेल, ट्रस्टी रिद्धीश जागीरदार एवं ट्रस्टी तरुण मेहता ने बंजारा हिल्स स्थित मंत्री कार्टर्स में तेलंगाना राज्य के मंत्री जी. विवेक, सीतारामबाग स्थित श्री जगन्नाथ मठ में महंत अच्युत रामानुजाचार्य, नारायणगुडा में

और गौरक्षकों को भी अभियान से जोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान किसी संस्था या संगठन के बैनर तले आयोजित नहीं होगा, बल्कि इसके प्रधान संरक्षक वेदलक्षणा गोमाता एवं अध्यक्ष नंदी बाबा (वृषभ) होंगे। यह अभियान गौमाता और नंदी बाबा को समर्पित रहेगा। रिद्धीश जागीरदार ने बताया कि आगामी 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 8.30 बजे इंदिरा पार्क के पास स्थित एन.टी.आर. गार्डन में गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपेगा। वहीं, अन्य प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को गो सम्मान आह्वान संबंधी ज्ञापन सौंपेंगे।



रसूलपुरा स्थित बी.ए.पी.एस. स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित चार दिक्सीय आध्यात्मिक पारायण महोत्सव में पं. जनमंगलदास स्वामी का अभिनंदन करते हुए आत्माचितनदास स्वामी, जसमत पटेल, रिद्धीश जागीरदार, घनश्याम पटेल एक अन्य।

